

भारत में सूखे की भौगोलिक विवेचना

अंकित सिंह

शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

भारत का उपमहाद्वीपीय आयाम, भौगोलिक स्थिति और मानसून का स्वरूप, भारत को सर्वाधिक खतरा-प्रवण देशों की पंक्ति में ला खड़ा करता है। भारत की अवस्थिति सूखे, बाढ़, चक्रवातों और भूकम्पीय घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ सूखा पड़ने का लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1801 से लेकर 2017 तक देश में 45 बार गंभीर सूखा पड़ा है। हाल के कुछ वर्षों में कमजोर मानसून का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है और बारिश की कमी से फसल की हानि, सूखे का सबसे आम रूप है जो हमारे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र को कमजोर करता है। सूखे के कारण मवेशियों की भी हानि होती है। इस कारण सूखे से बचाव के लिये इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

मूल शब्द मानसून, भौगोलिक स्थिति, चक्रवात

प्रस्तावना

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत में सूखे से प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन।
2. भारत में सूखे से निपटने के उपाय का अध्ययन।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत सरकारी प्रपत्रों, शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों का अध्ययन किया गया है, मानचित्रों का भी प्रयोग अध्ययन की सरलता के लिये किया गया है।

भारत में सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं नियंत्रण के उपाय

सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लम्बे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती रही है, भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19 प्रतिशत भाग और जनसंख्या का 12 प्रतिशत हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार-बार पड़ते हैं और जहाँ उनका असर अधिक है सूखे की तीव्रता के आधार पर अग्रलिखित भागों में बाँटा गया है—

(क) अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र

राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है।

(ख) अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र

इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्यप्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आन्ध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार,

तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखण्ड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल हैं।

(ग) मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र

इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखण्ड, तमिलनाडु में कोयंबटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है।

सूखे का प्रभाव व नियंत्रण

पर्यावरण तथा समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहत पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है, पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को विवश हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोगों को पेयजल सम्बन्धी बीमारियाँ, जैसे— ऑत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है।

सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों रूपों में होता है। अतः इसके निवारण में तैयार की जाने वाली योजनाओं में दोनों का समन्वय होना चाहिए। जहाँ एक ओर तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाईयाँ, पशुओं के लिये चारों और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल हैं। सूखे से निपटने के लिये दीर्घकालिक योजनाओं में, भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों से अल्पजल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, नदियों को जोड़ना और बाँध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण है। नदियों को जोड़ने के लिये द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।

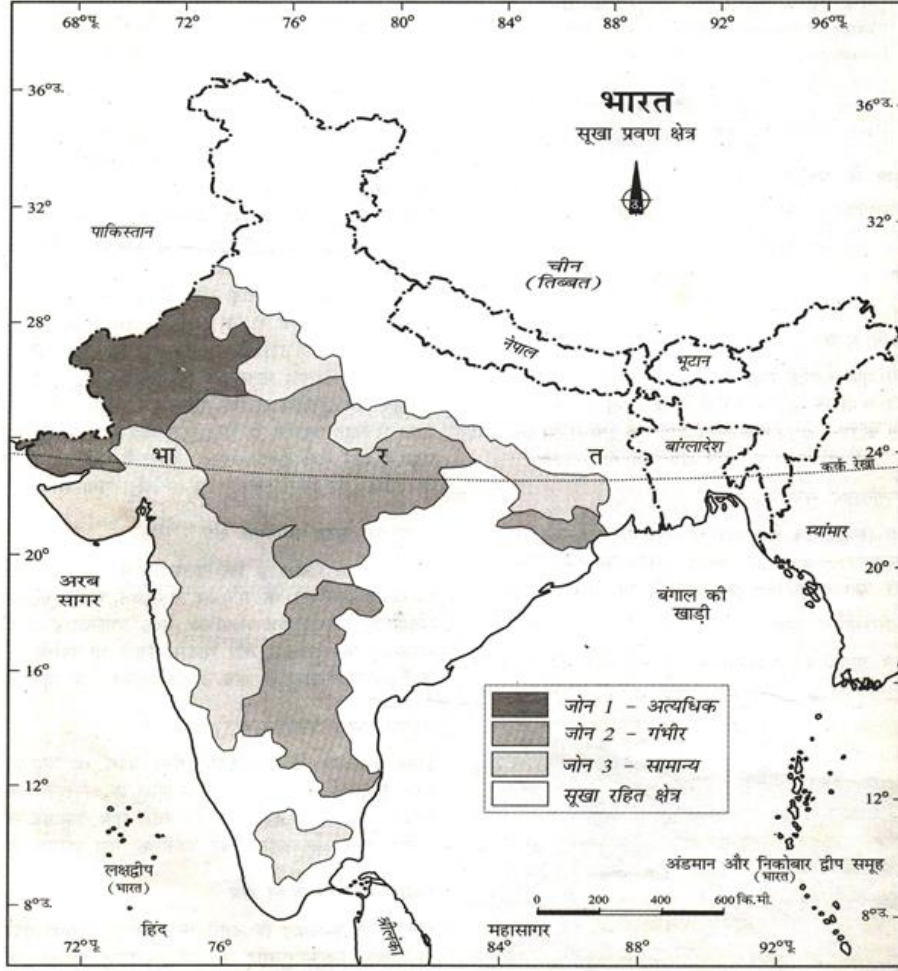
इसके अतिरिक्त सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार-प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल

संवलन, सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सूखे से निपटने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे प्रमुख कदमों में बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, लघुस्तरीय सिंचाई योजनाओं का विकास, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूखा राहत राशि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि वानिकी, आपदा राहत प्रबंधन आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि में बदलाव की बात करते हुये

संकर और उच्च उपज बीज, प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण पर अनुसंधान में अधिक निवेश कर सूक्ष्म सिंचाई के जरिए जल का किफायती उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान पर निवेश की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। इजराइल जैसे प्रौद्योगिकी सम्पन्न राष्ट्रों से कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्र में समझौते से सूखे पर प्रभावी नियंत्रण में अवश्य सहायता मिलेगी।



आकृति 1: भारत: सूखा प्रभावित क्षेत्र

सन्दर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, (UNDP) 2004: रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क : ए चैलेंज फार डेवलपमेंट, न्यूयार्क।
2. कार्टर, डब्लू, निक 1991 : डिजास्टर मैनेजमेंट ए डिजास्टर मैनेजर्स हैण्डबुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला।
3. साहनी, प्रदीप, धमेजा, अल्का एवं मेडुरी, उमा (संपा0) 2001 : डिजास्टर मिटिगेशन : एक्सपीरियंस एण्ड रिप्लेक्शन्स, प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. तिवारी, आर0 सी0, 2007 : भारत का भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
5. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, 2006 : भारत भौतिक पर्यावरण, नई दिल्ली।
6. सिंह, सविन्द्र, 2010 : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन,

इलाहाबाद।

7. रिपोर्ट ऑफ दी हाई पावर्ड कमेटी फॉर प्रीपिरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स 2001, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. [http:// www.ndm India.nic.in](http://www.ndm India.nic.in)